vinetur

नए व्यापार समझौते के तहत भारत ने न्यूज़ीलैंड की वाइन पर शुल्क 150% से घटाकर 50% किया

शुल्क में 10 साल तक होने वाली कटौती से उन उत्पादकों के लिए बड़ा बाज़ार खुल सकता है, जिनका भारत को वाइन निर्यात अब भी सालाना $500,000 से कम है

गुरुवार, 12 नवंबर 2026



भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होने के बाद न्यूज़ीलैंड के वाइन उत्पादकों को भारत में बेहतर बाज़ार पहुंच मिली है। इसके साथ ही शुल्कों में 10 साल तक कटौती की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिनकी वजह से इस बाज़ार में बिक्री लंबे समय से कम बनी हुई थी।

उद्योग संगठन New Zealand Winegrowers के अनुसार, समझौते के तहत पात्र न्यूज़ीलैंड वाइन पर शुल्क 150% से घटकर 50% या 25% हो जाएगा ; यह वाइन के मूल्य पर निर्भर करेगा। समझौते में वाइन के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का प्रावधान भी है। इसका मतलब है कि यदि भारत भविष्य में किसी अन्य देश के साथ व्यापार समझौते में वाइन पर बेहतर शुल्क शर्तें देता है, तो पात्र न्यूज़ीलैंड वाइन को भी स्वतः वही रियायत मिलेगी।

यह बदलाव भारत में न्यूज़ीलैंड की मौजूदा बिक्री के छोटे आधार से कहीं अधिक मायने रखता है। New Zealand Winegrowers ने बताया कि भारत को वाइन निर्यात से देश को सालाना $500,000 से कम की कमाई होती है और इस बाज़ार में निर्यात एक साल पहले की तुलना में 48% बढ़कर लगभग $438,000 से थोड़ा कम रहा। फिर भी, शुल्कों में क्रमिक कमी से भारत में वाइन आपूर्ति करने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे बदल सकती है और न्यूज़ीलैंड के निर्यातकों को बिक्री के स्रोतों में विविधता लाने का नया रास्ता मिल सकता है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब घरेलू स्तर पर सीमित आपूर्ति और वैश्विक बाज़ार की असमान स्थितियों के बीच उद्योग खुद को ढाल रहा है।

New Zealand Winegrowers की मुख्य कार्यकारी Anishka Jelicich ने कहा कि समझौते का तेज़ी से अनुमोदन पहले ही एक लाभ दिला चुका है, क्योंकि इससे अलग यूरोपीय संघ-भारत व्यापार समझौते के तहत तय की गईं तरजीही शर्तें हासिल हुईं। उन्होंने कहा कि शुल्क में ये कटौतियां उन रियायतों से अधिक थीं, जो यूरोपीय संघ का समझौता पहले लागू होने पर न्यूज़ीलैंड को मिलतीं।

यह समझौता शुल्क से आगे भी जाता है। वाइन और स्पिरिट के लिए एक विशेष परिशिष्ट तकनीकी मामलों, लेबलिंग और प्रमाणन पर कार्य समूह बनाता है। विनियमित बाज़ारों में उत्पादकों के प्रवेश और विस्तार को अक्सर यही क्षेत्र प्रभावित करते हैं। पेय कंपनियों के लिए ये नियम शीर्षक में दिखने वाली शुल्क कटौतियों जितने ही अहम हो सकते हैं, क्योंकि इनका असर उत्पाद की मंज़ूरी, अनुपालन लागत और वितरण की गति पर पड़ता है।

आयातित वाइन के लिए भारत अब भी अपेक्षाकृत छोटा बाज़ार है, लेकिन इसका आकार और वृद्धि निर्यातकों का ध्यान खींच रही है। New Zealand Winegrowers के मुताबिक, भारत में वाइन की खपत मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में केंद्रित है। इन तीन शहरों में देश की वाइन खपत का लगभग आधा हिस्सा है और यहां करीब 70 million लोग रहते हैं। मुंबई वाले महाराष्ट्र राज्य में मार्च 2026 तक के साल में वाइन की बिक्री रिकॉर्ड 13 million लीटर तक पहुंच गई। उद्योग संगठन के अनुसार, 2025 में भारत का वाइन आयात मात्रा के लिहाज़ से 14% बढ़ा।

न्यूज़ीलैंड के उत्पादक मांग के स्वरूप पर भी गौर कर रहे हैं। भारत के आयातित वाइन बाज़ार में रेड वाइन की हिस्सेदारी अच्छी-खासी है। New Zealand Winegrowers के अनुसार, इससे Sauvignon Blanc से इतर शैलियों के लिए भी जगह बन सकती है—Sauvignon Blanc वह श्रेणी है, जिसके साथ विदेशों में न्यूज़ीलैंड की वाइन को सबसे अधिक जोड़ा जाता है।

उद्योग जगत के अधिकारियों ने आगाह किया है कि केवल कम शुल्क सफलता की गारंटी नहीं देंगे। भारत की एकमात्र Master of Wine Sonal C Holland ने वेलिंगटन में New Zealand Winegrowers के Wine Business Forum में कहा कि व्यापार समझौता एक बड़ी बाधा हटाता है, लेकिन भारत में टिकाऊ वृद्धि के लिए धैर्य, लगातार निवेश और मज़बूत स्थानीय संबंध ज़रूरी होंगे। Jelicich ने कहा कि संगठन का ध्यान सदस्यों को व्यावहारिक बाज़ार जानकारी, हितधारकों से संपर्क और ब्रांड बनाने के लिए ज़मीनी अवसरों के ज़रिए बाज़ार का आकलन करने में मदद देने पर है।

इसी कोशिश के तहत New Zealand Winegrowers और New Zealand Trade and Enterprise नवंबर में होने वाले ProWine Mumbai व्यापार मेले में 20 कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल को ले जा रहे हैं।

भारत में खुलता यह अवसर ऐसे समय आया है, जब न्यूज़ीलैंड का वाइन उद्योग आपूर्ति और मांग में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सितंबर में जारी अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में New Zealand Winegrowers ने बताया कि जून 2026 तक के 12 महीनों में 306.2 million लीटर वाइन का निर्यात हुआ, जिसका मूल्य $2.108 billion था। निर्यात की बदौलत कुल बिक्री 8% बढ़ी। जून में समाप्त वर्ष के लिहाज़ से यह उद्योग का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा नतीजा था।

इसी दौरान, 2026 की फसल छोटी रही। 2026 के विंटेज में कुल करीब 440,000 टन अंगूर की पैदावार हुई, जो पिछले साल से 15% कम थी। New Zealand Winegrowers ने कहा कि कम पैदावार से उत्पादन मौजूदा बाज़ार मांग के करीब आया है। इससे पहले वैश्विक वाइन व्यापार के लिए कठिन दौर रहा था।

New Zealand Winegrowers के अध्यक्ष Fabian Yukich ने कहा कि दुनिया भर में वाइन उद्योग के लिए यह साल चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन न्यूज़ीलैंड के उत्पादक टिके रहे और ज़रूरी बदलाव कर रहे हैं। जुलाई में मुख्य कार्यकारी बनीं Jelicich ने कहा कि संगठन की संशोधित रणनीति का मकसद उत्पादकों और वाइनरी को बाज़ार, उत्पादन और निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए बेहतर जानकारी, पक्षसमर्थन और व्यावहारिक मदद देना है।

निर्यातकों के लिए भारत अब भी एक छोटा गंतव्य है। लेकिन शुल्क कटौती, प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं को भविष्य में मिलने वाली किसी भी बेहतर शर्त का स्वतः लाभ और तकनीकी बाधाओं से निपटने के लिए रूपरेखा—ये सभी न्यूज़ीलैंड की वाइन कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाज़ारों में से एक में प्रवेश का अधिक स्पष्ट रास्ता देते हैं। हालांकि, वहां उल्लेखनीय बिक्री खड़ी करने में कई साल लग सकते हैं।